Representation of Film Industry in N.F.D.C.

1030. SHRI K. T. KOSALRAM: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that prominent film organisations have urged Government to ensure equitable representation to all sections of the film industry from all over the country in the proposed National Film Development Corporation; and

(b) if so, the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI RAMDULARI SINHA): (a) Yes, Sir.

(b) Government is desirous of giving equitable representation to different sections concerning the film industry and the Board of the National Film Development Corporation is being constituted keeping this object in view.

New Kenil Worth Hotel, Calcutta

1031. SHRI NIHAL SINGH: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a)whether New Kenil Worth Hotel Private Limited, 1 & 2, Little Russel Street, Calcutta-7 was started and the number of partners of the hotel at the time of its formation and their number at present; and

(b) whether it is a fact that partners of the Hotel are violating company rules and whether Government have received any complaint against the Hotel in this connection and if so, the action taken so far thereon and if action has not been taken, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) New Kenil Worth Hotel Private Ltd. was registered in the State of West Bengal on 29th April, 1970. Being a Company there are no partners. Both at the time of formation and at present there are 3 directors in the company.

(b) No complaint has been received against the company. The directors of the company were however prosecuted, under section 210(5) of the Companies Act, 1956 and were fined Rs. 480 for non-laying of the Balance Sheet of the company as on 31st March, 1976 at the Annual General Meeting.

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास बस्तियों में सुविधाएं

1032. **श्री निहाल सिंह** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.—

(क) क्या शेष पुनर्वास समस्याओ पर विचार करने के लिए गठित किये गये कार्यवाही ग्रुप की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् सरकार ने 31 दिसम्बर, 1950 के पश्चात् पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई 175 बस्तियो में प्लाटधारियो को सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हा, तो क्या सभी प्लाटधारियो को सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं ; और

(ग) यदि नही, तो कितने प्लाटधारियो को सुविधाएं प्रदान नही की गई हैं ?

पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० क० बंगन) (क) कार्यकारी दल ने 1976 मे भूमियों के अधिग्रहण एवं भू-स्थलो के विकास द्वारा 1950 के बाद की 175 अनधिवासी बस्तियो को नियमित करने की सिफारिश की थी । भारत सरकार ने इन योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है जो अब पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं ।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि वह अपने भूमि विकास तथा योजना अधिनियम के उपबंधों के अधीन भूमि योजना समिति को प्रस्तुत किए जाने के लिए इन बस्तियो के सर्वेक्षण नक्शे तैयार कर रही है । उसने आगे सूचित किया है कि अधिग्रहण कार्यवाहियों को अन्तिम रूप देने तथा भूमियों का कब्जा लेने के बाद भू-स्थलों के विकास और प्लाटधारियों को हक देने के लिए कार्रवाई की जाएगी ।